



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2009/आषाढ़ 24, 1931

No. 407]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2009/ASADHA 24, 1931

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2009

भारत गणराज्य और ताजिकिस्तान गणराज्य के बीच
प्रत्यर्पण संधि

सा.का.नि. 524(अ).—जबकि भारत गणराज्य और ताजिकिस्तान गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि पर दुशान्बे में 14 नवम्बर, 2003 को हस्ताक्षर किए गए थे; और 18 फरवरी, 2009 को दुशान्बे में अनुसमर्थन दस्तावेज का आदान-प्रदान किया गया था और इस संधि के अनुच्छेद 21 के अनुसार यह करार अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान प्रदान किये जाने की तारीख से लागू हो गया है और जिस संधि में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

भारत गणराज्य और ताजिकिस्तान गणराज्य जिन्हें इसमें इसके बाद "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है ;

अपराधियों के अन्योन्य प्रत्यर्पण के लिए और प्रावधान करते हुए अपराधियों के दमन में दोनों पक्षों के सहयोग को और प्रभावी बनाने की इच्छा से ;

यह स्वीकार करते हुए कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ठोस उपाय आवश्यक हैं ;

नीचे दिए अनुसार सहमत हुए हैं ;

अनुच्छेद-1

प्रत्यर्पण के प्रति दायित्व

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इसकी संधि में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और शर्तों के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर अनुरोधकर्ता

2599 GI/2009

पक्ष के क्षेत्र में इस संधि के अनुच्छेद-दो में निर्दिष्टानुसार किसी प्रत्यर्पण अपराध को करने का आरोप लगाया जा रहा है अथवा सिद्ध-दोष है, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र के भीतर पाये जाने पर चाहे वह अपराध इस संधि के लागू होने से पहले अथवा बाद में किया गया हो, दूसरे संविदाकारी पक्ष को प्रत्यर्पित करने का वचन देता है ।

2. इस संधि के अनुच्छेद-दो में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रत्यर्पण ऐसे प्रत्यर्पण अपराध के संबंध में भी लागू होगा जो अनुरोधकर्ता पक्ष के क्षेत्र से बाहर किया गया हो, परन्तु जिसके संबंध में उसका क्षेत्राधिकार है, बशर्त अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के पास तदनुसंगी परिस्थितियों में ऐसे अपराध पर क्षेत्राधिकार होता। ऐसी परिस्थितियों में अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अपराध की गंभीरता सहित मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा ।

3. इस संधि के अनुच्छेद-दो में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रत्यर्पण किसी ऐसे प्रत्यर्पण अपराध के लिए भी प्राप्त होगा जिसमें वह अपराध अनुरोधकर्ता पक्ष के किसी नागरिक द्वारा किसी तीसरे देश में किया गया है और अनुरोधकर्ता पक्ष इस संधि के अनुच्छेद पन्द्रह के प्रावधानों के अधीन अपना क्षेत्राधिकार अपराधी की नागरिकता के आधार पर बनाता है ।

अनुच्छेद-2

प्रत्यर्पण अपराध

1. इस संधि के प्रयोजनार्थ प्रत्यर्पण अपराध ऐसे आचरण से बनता है जो प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के कानूनों के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा दिए जाने योग्य हो ।

2. कोई अपराध प्रत्यर्पण अपराध हो सकता है चाहे वह करारानुसार व राजस्व से संबंधित है अथवा पूरी तरह से वित्तीय स्वरूप का है ।

(1)

अनुच्छेद-3**संघटित अपराध**

इस संधि के अनुसार किसी प्रत्यर्पण अपराध के लिए प्रत्यर्पण प्राप्त होगा चाहे वांछित व्यक्ति का आचरण, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष में पूर्णतः अथवा अंशतः किया गया हो, बशर्ते इस आचरण, उसके प्रभावों, अथवा उसके अभिप्रेत प्रभावों को, कुल मिलाकर दोनों सविदाकारी पक्षों के कानूनों के अंतर्गत प्रत्यर्पण अपराध करने के समान समझा जाए।

अनुच्छेद-4**षडयंत्र करने, उकसाने और प्रयास करने के अपराध और अतिरिक्त क्षेत्रीय न्यायाधिकार**

1. किसी भी व्यक्ति के लिए दोनों सविदाकारी पक्षों के कानूनों के अंतर्गत किसी भी प्रत्यर्पण अपराध को अवप्रेरित करना, षडयंत्र करना अथवा करने का प्रयास करना, अथवा उकसाना अथवा अपराध करने में साथी के रूप में भाग लेना एक अपराध होगा।

2. दोनों सविदाकारी पक्षों के कानूनों के अंतर्गत सविदाकारी पक्ष के किसी नागरिक के लिए उसके क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर कोई अपराध करना भी अपराध होगा।

अनुच्छेद-5**प्रत्यर्पण से इन्कार करने के लिए आधार**

1. किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता यदि ;
 - 1.1 वह अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का नागरिक है; अथवा
 - 1.2 वह अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष को सन्तुष्ट पर दे कि प्रत्यर्पित कर दिए जाने पर उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता अथवा राजनीतिक विचारधारा के कारण उसके मुकदमे में उसे क्षति पहुंचाई जा सकती है अथवा सजा दी जा सकती है; अथवा
 - 1.3 वह अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष को सन्तुष्ट कर दे कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कारणों से उसे प्रत्यर्पित करना अन्यायपूर्ण और दमनकारी होगा ;
 - 1.3.1 अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानून के अंतर्गत आपराधिक प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए अथवा सजा पूरी करने के लिए अथवा अन्य कानूनी आधार पर समय-सीमा समाप्त हो जाना ;
 - 1.3.2 न्याय के हित में उसके विरुद्ध आरोप न लगाए गए हों ; अथवा
 - 1.4 अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानून के अंतर्गत प्रत्यर्पण किए जाने की अनुमति न हो ;
 - 1.5 जिस अपराध के लिए वह आरोपित है अथवा सिद्धदोष है, ऐसा सैन्य अपराध है जो सामान्य दण्ड कानून के अंतर्गत अपराध नहीं है ;

2. ऐसे व्यक्ति का भी प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा यदि जिस अपराध के संबंध में उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उसके

लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष में उसके विरुद्ध पहले ही कार्यवाही की गई है और उसे सिद्ध-दोष ठहराया गया है अथवा उसे छोड़ दिया गया है।

3. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा प्रत्यर्पण से इन्कार किया जा सकता है बशर्ते कि जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग की गई है उस पक्ष की अदालतों में प्रत्यर्पण अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता हो।

अनुच्छेद-6**अभियोजन की बाध्यता**

1. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार इस संधि के अनुच्छेद पांच के पैरा 3 में उल्लिखित कारणों के आधार पर प्रत्यर्पण का अनुरोध अस्वीकार कर देता है तो वह मुकदमा चलाये जाने के लिए इस मामले को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसे मामले में अभियोजन न चलाने का निर्णय लेते हैं तो प्रत्यर्पण के अनुरोध पर इस संधि के अनुरूप पुनः विचार किया जाएगा।

अनुच्छेद-7**अपने नागरिकों को प्रत्यर्पित नहीं करने के परिणाम**

यदि इस संधि के अनुच्छेद पांच के पैरा 1.1 के अनुसरण में प्रत्यर्पण से इन्कार किया जाता है, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अपने कानूनों के अनुसरण में उसी अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति के लिए आपराधिक अभियोजन आरंभ करेगा। इसके लिए अनुरोधकर्ता पक्ष अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष को संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य स्थानांतरित करेगा।

अनुच्छेद-8**प्रत्यर्पण तथा अस्थायी प्रत्यर्पण का स्थगन**

1. यदि प्रत्यर्पित किये जाने वाले व्यक्ति पर अभियोजन चलाया जा रहा है अथवा वह किसी अन्य अपराध के लिए अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य में सजा काट रहा है तो मामले की कार्रवाई समाप्त होने, सजा की समाप्ति अथवा मुक्ति, अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा जैसा सुझाव दिया जाए, तक के लिए प्रत्यर्पण स्थगित कर दिया जा सकता है।

2. यदि प्रत्यर्पण के स्थगन से निर्धारित अवधि समाप्त होती है अथवा जांच में बाधा पहुंचती है तो अनुरोधकर्ता पक्ष के विशेष अनुरोध पर उस व्यक्ति को अस्थायी तौर पर प्रत्यर्पित किया जा सकता है।

3. अस्थायी तौर पर प्रत्यर्पित व्यक्ति को मामले की कार्रवाई समाप्त होने के तत्काल परचात् अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य को वापस भेज देना चाहिए।

अनुच्छेद-9**प्रत्यर्पण प्रक्रिया**

1. प्रत्यर्पण का अनुरोध राजनयिक माध्यमों के जरिए किया जाएगा।

2. अनुरोध के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे :

- 2.1 उस व्यक्ति का नाम तथा उपनाम जिसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, उसकी नागरिकता के संबंध में सूचना, निवास स्थान अथवा पता-ठिकाना तथा अन्य संगत आंकड़े और यदि संभव हो, तो व्यक्ति के रंग-रूप का विवरण, उसका फोटो एवं उंगलियों के निशान ;
- 2.2 उस अपराध के तथ्यों का विवरण जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है; तथा
- 2.3 संगत कानून का पाठ;
 - 2.3.1 उक्त अपराध की परिभाषा; और
 - 2.3.2 उक्त अपराध के लिए सजा निर्धारित करना ।

3. ऊपर दी गई सूचना के अतिरिक्त मुकदमे के लिए प्रत्यर्पण के अनुरोध के साथ उस विषय के संबंध में अनुरोधकर्ता पक्ष के न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट संलग्न होना चाहिए ।

4. यदि अनुरोध ऐसे व्यक्ति के संबंध में है जिसे दोषी ठहराया गया हो और सजा दे दी गई हो, तो इसके साथ निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा वह विवरण, कि वह व्यक्ति अब दोषसिद्धि अथवा सजा पर प्रश्न उठाने के लिए हकदार नहीं है तथा कितनी सजा पूरी नहीं हुई है, दर्शाने वाला विवरण ।

5. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष यह समझता है कि इस सौंधि के प्रयोजनार्थ दिया गया साक्ष्य अथवा सूचना अनुरोध के अनुसार निर्णय लेने के उद्देश्य से पर्याप्त नहीं है, तो उपयुक्त समय के भीतर अतिरिक्त साक्ष्य अथवा सूचना प्रस्तुत की जाएगी ।

अनुच्छेद 10

अनन्तिम गिरफ्तारी

1. तात्कालिक मामलों में अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों को प्रत्यर्पणको अनुरोध प्राप्त होने से पहले राजनयिक माध्यमों अथवा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो-इन्टरपोल को पहले किए गए अनुरोध पर उसके कानून के अनुसार अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति को अनन्तिम रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है । इस अनुरोध में उक्त व्यक्ति के प्रत्यर्पण तथा गिरफ्तारी वारंट की मौजूदगी का विवरण, और यदि वह व्यक्ति जिसकी मांग की गई है, सिद्धदोषी है, तो उसके विरुद्ध सिद्धदोष का आदेश; तथा यदि उपलब्ध हो तो इस सौंधि के अनुच्छेद-नौ के पैराग्राफ 2.1 तथा 2.3 में उल्लिखित डाटा और इस प्रकार की अन्य सूचना, यदि कोई हो, जो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के प्रदेश में किए गए अपराध अथवा सिद्धदोष व्यक्ति के संबंध में गिरफ्तारी वारंट को औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए आवश्यक हो, के आशय का विवरण होगा ।

2. किसी व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर इस प्रकार का अनुरोध उसके गिरफ्तार होने की तारीख से 60 दिन की समाप्ति पर प्रस्तुत करना होगा, यदि उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ हो ।

यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध बाद में प्राप्त हुआ है तो वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए यह प्रावधान आगे की कार्रवाहियों को आरम्भ करने से नहीं रोकेगा ।

अनुच्छेद 11

विशिष्टता का नियम

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष की पूर्व सहमति के बिना, अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा उस अपराध के सिवाय जिसके लिए प्रत्यर्पण की मंजूरी दी गई है और उसका प्रत्यर्पण प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्रमाणित तथ्यों द्वारा दूसरे किसी छोटे अपराध के लिए प्रत्यर्पित किए गए व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है अथवा सजा नहीं दी जा सकती है और न ही अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष की पूर्व सहमति के बिना ऐसे व्यक्ति को किसी तीसरे राज्य को प्रत्यर्पित किया जा सकता है ।

2. निम्नलिखित के लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष की सहमति अपेक्षित नहीं है यदि :

2.1 चले जाने के अवसर के बावजूद प्रत्यर्पित व्यक्ति ने आपराधिक अभियोजन की समाप्ति, सजा दिए जाने अथवा अन्य किसी विधिक आधार पर रिहाई के बाद 30 दिन के भीतर अनुरोधकर्ता पक्ष के प्रदेश को नहीं छोड़ा है । ऐसी अवधि को उस समयावधि में शामिल किया हुआ न समझा जाए जिसमें प्रत्यर्पित व्यक्ति अपने नियंत्रण के बाहर के कारणों की वजह से अनुरोधकर्ता पक्ष के प्रदेश को छोड़ने में समर्थ नहीं हुआ;

2.2 यदि प्रत्यर्पित व्यक्ति एक बार अनुरोधकर्ता पक्ष के प्रदेश को छोड़ने के बाद स्वेच्छा से वहां वापिस आ जाता है ।

3. व्यक्ति के अनुरोधकर्ता पक्ष के पास वापिस आने के बाद किए गए अपराधों अथवा ऐसे अपराधों के संबंध में उत्पन्न मामलों में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ-1 के प्रावधान लागू नहीं होंगे ।

अनुच्छेद-12

दस्तावेजों और साक्ष्य को मान्यता देना

1. किसी सविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में निर्धारित प्रपत्र में उसके कानूनों के अनुसार सक्षम न्यायालयों अथवा अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी अथवा अधिप्रमाणित दस्तावेजों और अधिलेखबद्ध बयानों को दूसरे सविदाकारी पक्ष के प्रदेश में किसी अधिप्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी ।

2. दोनों सविदाकारी पक्षों में किसी एक सविदाकारी पक्ष के प्रदेश में दस्तावेजों को सार्वजनिक माना जाता है तो दूसरे सविदाकारी पक्ष के प्रदेश में भी वह सार्वजनिक दस्तावेजों का साक्ष्य होगा ।

अनुच्छेद-13

प्रतियोगी अनुरोध

1. यदि एक ही अपराध अथवा विभिन्न अपराधों के लिए एक सविदाकारी पक्ष और किसी तीसरे राज्य, जिसके साथ

अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के साथ प्रत्यर्पण संधि है, से प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किए जाते हैं तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष निश्चय करेगा कि व्यक्ति को किसको प्रत्यर्पित किया जाएगा और वह सविदाकारी पक्ष को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

अनुच्छेद-14

मृत्यु दण्ड

यदि वांछित व्यक्ति उस अपराध के लिए अनुरोधकर्ता पक्ष के कानून के अंतर्गत मृत्यु दण्ड का अधिकारी है, जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, परन्तु अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष का कानून उस अपराध के लिए मृत्यु दण्ड नहीं देता है, प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है जब तक कि अनुरोधकर्ता पक्ष ऐसे आश्वासन नहीं दे देता कि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष पर्याप्त रूप में समझता है कि मृत्यु दण्ड निष्पादित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद-15

स्थानांतरण

1. प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के स्थानांतरण के तौर-तरीकों को दोनों सविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आपसी रूप में सहमति से तैयार किया जाएगा।

2. अनुरोधकर्ता पक्ष वांछित व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्र से अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष की सहमति से एक महीने अथवा अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा स्वीकृत अधिक अवधि के भीतर ले जाएगा। यदि व्यक्ति को उस अवधि के भीतर नहीं हटाया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष उसी अपराध के लिये प्रत्यर्पण से इंकार कर सकता है।

अनुच्छेद-16

अपराध से सम्बन्ध सामानों का हस्तान्तरण

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष, अपने विधान की सीमाओं के भीतर प्रत्यर्पित किए गए व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए प्रयोग किए गए सामान के लिए अनुरोधकर्ता पक्ष के अनुरोध पर हस्तान्तरण करेगा।

2. उपरोक्त सामान का हस्तान्तरण उन मामलों में भी किया जाएगा जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाने, उसके फरार हो जाने अथवा अन्य किसी कारण से यह प्रत्यर्पण लागू नहीं हो सकता।

3. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष इस अनुरोध के पैरा-1 में उल्लिखित सामानों के हस्तान्तरण को अस्थायी रूप से स्थगित कर सकता है यदि ऐसी कार्रवाईयों के अंत तक किसी अन्य आपराधिक मामलों के संबंध में शुरू की गई कार्रवाईयों के लिए अपेक्षित है।

4. अनुरोधकर्ता पक्ष को हस्तांतरित सामान पर तीसरे व्यक्ति का अधिकार बरकरार रहेगा। कार्रवाई के खत्म होने पर अनुरोधकर्ता पक्ष इस सामान को अपने क्षेत्र में उनके मालिकों को लौटा देगा। यदि मालिक अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के क्षेत्र में है तो सामान उस पक्ष को

उन्हें हस्तांतरित किए जाने के लिए दिया जाएगा। यदि मालिक किसी तीसरे देश के क्षेत्र में है तो सामान उन्हें अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा बिना कोई खर्च दिए लौटा दिया जाएगा।

5. सम्पन्न और धनराशि का हस्तान्तरण अनुरोधकर्ता पक्ष के विधान के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सीमाओं के भीतर ही किया जाएगा।

अनुच्छेद-17

प्रत्यर्पण में परस्पर विधिक सहायता

प्रत्येक सविदाकारी पक्ष अपने कानून द्वारा अनुमति प्राप्त सीमा तक उस अपराध के संबंध में फौजदारी मामलों में परस्पर विधिक सहायता के व्यापक संभाव्य उपाय दूसरे के लिए करेगा जिसके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया गया है।

अनुच्छेद-18

प्रत्यर्पण पर व्यय

प्रत्यर्पण से सम्बन्धित सभी व्यय उस सविदाकारी पक्ष द्वारा वहन किए जायेंगे जिसके भूक्षेत्र में वह अपराध हुआ हो। सविदाकारी पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा अन्य सविदाकारी पक्ष के भूक्षेत्र के माध्यम से तीसरे पक्ष से प्रत्यर्पित व्यक्ति के मार्गस्थ परिवहन पर हुए व्यय को प्रभावित सविदाकारी पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

अनुच्छेद-19

भाषाएं

वर्तमान संधि का अनुपालन करते हुए, सविदाकारी पक्ष अपनी राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग करते हुए साथ में अन्य सविदाकारी पक्ष की राष्ट्रीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद संलग्न करेंगे।

अनुच्छेद-20

अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय/संधियां

यह संधि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों/संधियों जिनके सविदाकारी पक्ष हस्ताक्षरकर्ता हैं, से उत्पन्न सविदाकारी पक्षों के अधिकारों तथा बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुच्छेद-21

अनुसमर्थन और समापन

1. यह संधि अनुसमर्थन के अध्वधीन होगी और यह अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. दोनों में से कोई भी सविदाकारी पक्ष राजनयिक माध्यमों के जरिए अन्य सविदाकारी पक्ष को नोटिस देकर किसी भी समय इस संधि को समाप्त कर सकता है; और यदि इस प्रकार का नोटिस दिया जाता है तो यह संधि नोटिस के प्राप्त होने की तारीख के छह माह पश्चात् समाप्त मानी जाएगी।

जिसके सक्षम में निम्नलिखित अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने अपने-अपने प्राधिकारियों से विधिक रूप से प्राधिकृत होकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज, दुशान्बे में वर्ष दो हजार तीन के नवम्बर माह के 14वें दिन हिन्दी, ताजिक, रूसी और अंग्रेजी भाषाओं में सम्मन, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।

अतः अब प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उप-धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा निदेश करती है कि अध्याय-III को छोड़कर उक्त अधिनियम के प्रावधान इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ताजिकिस्तान गणराज्य पर लागू होंगे।

[टी-413/08/2003]

पी. एम. मोणा, संयुक्त सचिव (कॉन्सुलर)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2009

**EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC
OF INDIA
AND**

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

G.S.R. 524(E).—Whereas the Extradition Treaty between the Republic of India and the Republic of Tajikistan was signed at Dushanbe on 14 November, 2003; and the Instruments of Ratification also exchanged at Dushanbe on 18th February, 2009 and as per Article 21 of the Treaty, it has entered into force on the date of exchange of the instruments of ratification, and which Treaty provides as follows :

The Republic of India and the Republic of Tajikistan; hereinafter referred to as the "Contracting Parties";

Desiring to make more effective the cooperation of the two Parties in the suppression of crime by making further provision for the reciprocal extradition of offenders;

Recognizing that concrete steps are necessary to combat terrorism;

Have agreed as follows :

Article 1

Obligation to Extradite

1. Each Contracting Party undertakes to extradite to the other Contracting Party in the circumstances and subject to the conditions specified in this Treaty, any person who being accused or convicted of an extradition offence as described in Article 2 of the Treaty, committed within the territory of the Requesting Party, is found within the territory of the Requested Party, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

2. Extradition shall also be available in respect of an extradition offence as described in Article 2 of this Treaty committed outside the territory of the Requesting Party

25999709-2

but in respect of which it has jurisdiction, if the Requested Party would, in corresponding circumstances, have jurisdiction over such an offence. In such circumstances the Requested Party shall have regard to all the circumstances of the case including the seriousness of the offence.

3. Extradition shall also be available for an extradition offence as described in Article 2 of this Treaty, if it is committed in a third State by a citizen of the Requesting Party and it bases its jurisdiction on the citizenship of the offender, subject to the provisions under Article 15 of the Treaty.

Article 2

Extradition Offences

1. An extradition offence for the purposes of the Treaty is constituted by conduct which under the laws of each Contracting Party is punishable by a term of imprisonment for a period of at least one year.

2. An offence may be an extradition offence notwithstanding that it relates to taxation or revenue or is one of a purely fiscal character.

Article 3

Composite Offences

Extradition shall be available in accordance with this Treaty for an extradition offence, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested Party, if this conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extradition offence under the laws of both the Contracting Parties.

Article 4

Offences of conspiracy, incitement and attempt, and extra-territorial jurisdiction

1. It shall be an offence under the laws of both the Contracting Parties for any person to abet, conspire or attempt to commit or incite or participate as an accomplice in the commission of, any extradition offence.

2. It shall also be an offence under the laws of both the Contracting Parties, for any citizen of a Contracting Party to commit any offence in any place beyond its territory.

Article 5

Grounds for Refusal of Extradition

1. A person may not be extradited if :

1.1 he is a citizen of the Requested Party; or

1.2 he satisfies the Requested Party that he might, if extradited, be prejudiced at his trial or be punished, by reason of his race, religion, nationality or political opinions; or

1.3 he satisfies the Requested Party that it would, having regard to all the circumstances, be unjust or oppressive to extradite him by reason of :

1.3.1 the expiry of the limitation-period for initiating the criminal proceedings under the legislation of the Requested Party or for execution of a sentence, or on other legal grounds;

1.3.2 the accusation against him having not been made in the interests of justice; or

1.4 the extradition is not permitted according to the laws of the Requested Party;

1.5 the offence of which he is accused or convicted is a military offence which is not also an offence under the general criminal law.

2. A person shall also not be extradited if in respect of the offence for which his extradition is requested, he has been previously proceeded against in the Requested Party, and convicted or acquitted.

3. The request for extradition may be refused by the Requested Party if the person whose extradition is sought may be tried for the extradition offence in the courts of that Party.

Article 6

Obligation to Prosecute

1. Where the Requested Party refuses a request for extradition for the reason set out in paragraph 3 of Article 5 of this Treaty, it shall submit the case to its competent authorities for prosecution.

2. If the competent authorities decide not to prosecute in such a case, the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Treaty.

Article 7

Consequences of Non-extradition of own citizens

If according to paragraph 1.1 of Article 5 of this Treaty, extradition is refused, the Requested Party, shall initiate criminal prosecution against such person for the same offence according to its laws. For this the Requesting Party shall transfer to the Requested Party the relevant documents and evidence.

Article 8

Postponement of Extradition & Temporary Extradition

1. If the person to be extradited is being prosecuted or serving sentence for another crime in the territory of the Requested Party, the extradition may be postponed till the end of the proceedings of the case, end of sentence or release, which shall be advised to the Requesting Party.

2. If the postponement of extradition can cause the expiration of the limitation or impede the investigation, the person can be extradited temporarily under a special request of the Requesting Party.

3. The temporarily extradited person must be returned to the Requested party immediately after the end of the proceedings of the case:

Article 9

Extradition Procedures

1. The request for extradition shall be made through diplomatic channels.

2. The request shall be accompanied by :

2.1 the name and surname (petronym) of the person whose extradition is requested, information on his citizenship, place of residence or whereabouts and, other pertaining data, as well as, if possible, the description of the person's appearance, his photographs and fingerprints;

2.2 a statement of the facts of the offence for which extradition is requested; and

2.3 the text, of the corresponding law :

2.3.1. defining that offence; and

2.3.2. prescribing the punishment for that offence.

3. The request for extradition for the prosecution, besides the information specified above, must be accompanied by the warrant of arrest issued by a competent court or authority of the Requesting Party.

4. If the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be accompanied by a certified copy of the judgement and a statement that the person is no longer entitled to question the conviction or sentence and showing how much of sentence has not been carried out.

5. If the Requested Party considers that the evidence produced or information supplied for the purposes of this Treaty is not sufficient in order to enable a decision to be taken as to the request, additional evidence or information shall be submitted within a reasonable time.

Article 10

Provisional Arrest

1. In urgent cases a person may be provisionally arrested by the Requested Party, in accordance with its law, on the request of the competent authorities of the Requesting Party, made either through Diplomatic Channels or the National Central, Bureau of International Criminal Police Organisation - INTERPOL, before the receiving of the request for extradition. The request shall contain an indication of intention to request the extradition of, that person and a statement of existence of a warrant of arrest or a conviction against him; and if available, the data specified in paragraphs 2.1 and 2.3 of Article 9 of this Treaty and such further information, if any, as would be necessary to justify the issue of a warrant of arrest had the offence been committed, or the person been convicted, in the territory of the Requested Party.

2. A person arrested upon such a request shall be set at liberty upon the expiration of 60 days from the date of his arrest if a request for his extradition shall not have been received. This provision shall not prevent the institution of further proceedings for the extradition of the person sought if a request for extradition is subsequently received.

Article 11

Rule of Speciality

1. The extradited person may not without consent of the Requested Party, be prosecuted or punished in the Requesting Party for the offence other than that, for which extradition has been granted and any lesser offence disclosed by the facts proved for the purpose of securing his extradition, nor may such a person, without consent of the Requested Party, be extradited to third State;

2. The consent of the Requested Party is not required if:

2.1. the extradited person has not left, though had the opportunity, the territory of the Requesting Party within 30 days after termination of the criminal prosecution, serving of the sentence or release on any legal ground. Such period shall not be deemed to include the period of time during which the extradited person is unable to leave the territory of the Requesting Party for reasons beyond his control;

2.2. if the extradited person, once having left the territory of the Requesting Party, voluntarily returns there.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to offences committed after the return of person to the Requesting Party or matters arising in relation to such offences.

Article 12

Recognition of Documents and Evidence

1. Documents issued or certified and statements recorded by competent Courts or other authorities in the prescribed form in the territory of one Contracting Party as per its laws shall not require any form of authentication in the territory of the other Contracting Party.

2. Documents considered as public in the territory of one of the Contracting Parties shall have the evidential force of public documents also in the territory of the other Contracting Party.

Article 13

Competing Requests

If extradition of the same person whether for the same offence or for different offences is requested by a Contracting Party and a third State with which the Requested Party has an extradition arrangement, the Requested Party shall determine the State to which the person shall be extradited, and shall not be obliged to give preference to the Contracting Party.

Article 14

Capital Punishment

If under the law of the Requesting party the person sought is liable to the death penalty for the offence for which his extradition is requested, but the law of the Requested Party does not provide for the death penalty for the same offence, extradition may be refused unless the Requesting Party gives such assurances as the Requested Party considers sufficient that the death penalty will not be carried out.

Article 15

Transfer

1. The modalities of transfer of the person to be extradited shall be agreed upon by the competent authorities of both the Contracting Parties as mutually convenient.

2. The Requesting Party shall take the person sought from the territory of the Requested Party within one month of the consent of Requested Party to extradite or such longer period as may permitted under the law of the Requested Party. If the person is not removed within that period, the Requested Party may refuse to extradite him for the same offence.

Article 16

Transfer of Articles connected with Crime

1. The Requested Party shall, within the limits of its legislation, transfer by the request of Requesting Party the Articles used for committing crime by the person being extradited, Articles bearing crime traces or crime proceeds.

2. The above Articles shall be transferred also in cases when the extradition cannot be effected if the person died, fled or due to other reasons.

3. The Requested Party may temporarily postpone the transfer of the Articles referred to the paragraph 1 of this Article if they are required for proceedings instituted in connection with another criminal case till the end of such proceedings.

4. The rights of third persons to the articles transferred to the Requesting Party shall remain in force. Upon termination of the proceedings the Requesting Party shall return these Articles to their owners in its territory. If the owners are in the territory of the Requested Party the articles are to be returned to it for the transfer to them. If the owners are in the territory of a third country the articles shall be returned to them by the Requesting Party without charge.

5. The transfer of the Articles and of money shall be effected within the limits provided for by the legislation of the Requested Party.

Article 17**Mutual Legal Assistance in Extradition**

Each Contracting Party shall, to the extent permitted by its law, afford the other the widest possible measure of mutual legal assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

Article 18**Expenses on Extradition**

All expenses related to the extradition shall be borne by the Contracting Party in whose territory the same occurred. The expenses caused by the transit transportation of the extradited person by one of the Contracting Parties from a third State through the territory of the other Contracting Party shall be borne by the Contracting Party effecting the transit.

Article 19**Languages**

While complying with the present Treaty, the Contracting Parties shall use their national language attaching the translation in the national language of the other Contracting Party or in the English language.

Article 20**International Conventions/Treaties**

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties arising from other International Conventions/Treaties to which the Contracting Parties are signatories.

Article 21**Ratification and Termination**

1. This Treaty is subject to ratification and it shall enter into force on the date of exchange of the instruments of ratification.

2. Either of the Contracting Parties may terminate this Treaty at any time by giving notice to the other Contracting Party through the diplomatic channel; and if such notice is given the Treaty shall cease to have effect six months after the receipt of the notice.

In witness whereof the undersigned being duly authorized thereto by their respective Authorities, have signed this Treaty.

Done in duplicate at Dushanbe this 14th November 2003 in Hindi, Tajik, Russian and English languages, each version being equally authentic. In case of any interpretation difference, the English text shall prevail.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to the Republic of Tajikistan with effect from the date of the publication of this notification.

[T-413/08/2003]

P. M. MEENA, Jt. Secy. (Consular)